साप्ताहिक
डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21
RNI-MPHIN/2015/72544
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 06-12 दिसंबर 2021, वर्ष-7, अंक-36
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

गौ-ग्रास अभियान

जागत गांव हमार

..आओ, गौमाता को दें चारा और कमाएं पुण्य...

सनातन हिंदू धर्म के तीन प्रमुख आधार हैं- गाय, गंगा और गायत्री। ये तीनों आधार मां स्वरूप हैं। हमारे पुनीत धर्मग्रंथों में जिन सात पुण्यों को अर्जित करने का निर्देश दिया गया है, उनमें गौमाता की सेवा को शीर्ष पर रखा गया है। गाय की सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम उसके लिए ग्रास यानी चारा-पानी की व्यवस्था करें। गौ-ग्रास के लिए प्रतिदिन 10 रुपए का दान दीजिए...। यह छोटी सी धनराशि आपके लिए उत्तम पुण्य का सृजन करेगी, आपका यह योगदान गाय का पालन, पोषण, संरक्षण करेगा। सनातन हिंदू धर्म समृद्ध होगा...आओ, गौमाता को दें चारा और पुण्य कमाएं।

अपना अंशदान यहां दें: मप्र गौ संवर्धन बोर्ड
बैंक खाता नंबर: 1007852744
आईएफएससी कोड: SBIN0030388
एसबीआई शाखा: नर्मदा भवन, भोपाल

सहयोग के लिए आभार

मप्र गौसंवर्धन बोर्ड की पहल चरनोई विकास मिशन को सरकार ने दी सहमति

गाय को गांव में मिलेगा चारागाह

अरविंद मिश्रा, भोपाल।

मध्यप्रदेश में अब गायों के लिए गांव में ही चारागाह के स्थान तय किए जाएंगे। मप्र गौ संवर्धन बोर्ड की पहल पर शिवराज सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र का दो प्रतिशत रकबा गायों के चारागाह के लिए आरक्षित किया जाएगा। भूमि चयन और संवर्धन का यह काम चरनोई विकास मिशन के माध्यम से किया जाएगा। इस मिशन के गठन की औपचारिकता पूरी करने की कवायद शुरू हो गई है। यह खुलासा मप्र गौ संवर्द्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद ने '**जागत गांव हमार**' से खास बातचीत के दौरान किया। उन्होंने बताया कि यह निर्णय बीते 18 नवंबर को लिया गया है। इसके बाद चरनोई विकास मिशन के नियम निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञों से इसके लिए सलाह भी ली जाएगी। इसके बाद इस प्रस्ताव सरकार के पास लागू करने के लिए भेजा जाएगा। इसमें कई विभाग भी शामिल हैं। इसलिए उम्मीद है कि उनके सहयोग से यह मिशन गायों को पर्याप्त भोजन सुनिश्चित कराने में सफल रहेगा। इतना ही नहीं, इसके बाद गांव में बेकार पड़ी सरकार की भूमि का जहां सदुपयोग सुनिश्चित होगा। वहीं अतिक्रमण से भी बचाया जा सकेगा। इसके अलावा गौ सदन के माध्यम से भंग में हुए 72 सौ एकड़ भूमि बहाल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं।

- » चरनोई विकास मिशन के माध्यम से जमीन चिंहित करेंगे जमीन
- » सागर, जबलपुर, पन्ना, टीकमगढ़, शिवपुरी, सिहोर, खरगोन, मंदसौर में गौ-सदन होंगे बहाल
- » मध्यप्रदेश में 6700 एकड़ जमीन, इनमें 36 सौ एकड़ जमीन सिर्फ सागर जिले में

शिवराज भी आए आगे

छत्तीसगढ़ राज्य बन जाने के बाद रायपुर व बिलासपुर के अलग होने के कारण 6700 एकड़ मप्र में है। इनमें 36 सौ एकड़ जमीन सिर्फ सागर जिले में है। शेष जबलपुर, पन्ना, टीकमगढ़, शिवपुरी, सिहोर, खरगोन और मंदसौर है। जिसकी अभी हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा कर दी है कि बंद हो चुके आठ गौ-सदनों को फिर से चालू किया जाएगा। जिसमें उक्त जिले शामिल हैं।

रोजगार भी मिलेगा

मिशन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। क्योंकि गौ संवर्द्धन बोर्ड के अधीन काम करने वाला चरनोई विकास मिशन चारा उर्पाजन का काम स्थानीय स्तर पर कराएगा। इसमें ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली स्व सहायता समितियां भी शामिल हो सकती हैं। एक निश्चित अवधि के लिए सौंपी गई इस चरनोई भूमि के बदले इनसे एक मुश्त राशि जमा कराई जाएगी।

मिशन से जुड़ेगा राजस्व विभाग

गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि जिन ग्रामों या पंचायतों में चरनोई भूमि नहीं है, वहां के नागरिक बताएं है कि गांव के बाहर रिक्त सरकारी भूमि कहां है। हम राजस्व विभाग के अधिकारियों के माध्यम से उसे चरनोई भूमि के लिए आरक्षित कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

दानदाताओं को आयकर में छूट

स्वामी अखिलेश्वरानंद बताया कि गौ-संवर्द्धन बोर्ड ने अपनी वेबसाईट पर एक पोर्टल जारी किया है। जो भी गौ-भक्त चारा-भूसा,पशु आहार, गौ-ग्रास के निमित्त आर्थिक सहयोग करना चाहें। वेबसाईट जरिए ऑनलाइन अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। दान की हुई राशि पर आयकर की छूट रहेगी। बोर्ड की अपेक्षा न्यूनतम राशि 3650 रुपए है। अधिकतम जितनी देना चाहें दें सकते हैं। लोग चाहें तो अपनी पसंद की गौ-शाला का नाम भी सूचित कर सकते हैं। ऐसी गौ-शाला जो गौ-संवर्द्धन बोर्ड, भोपाल द्वारा पंजीकृत हो। दान राशि पोर्टल के माध्यम से ही आना चाहिए। इस माध्यम से हिसाब-किताब में आसानी होगी। पोर्टल पर दानदाता का नाम भी शो होता है। सीधे बैंक खाते में राशि भेजने वाले आरटीजीएस कर सकते हैं। राशि भेजने वाले दानदाता अपने नाम की सूचना अवश्य करें।

टंट्या मामा के बलिदान दिवस: सीएम शिवराज की घोषणा

समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी वनोपज

- » अगले चार साल में किसी को बिना आवास नहीं रहने देंगे
- » राशन आपके ग्राम योजना में गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा राशन
- » जनजातीय बहनों के घर में नल के द्वारा पहुंचाया जाएगा जल
- » हेरिटेज शराब को प्रोत्साहित करेगी नई आबकारी नीति

भोपाल।

जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस पर राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय भाइयों की वनोपज को माटी के मोल नहीं बिकने देंगे। महुआ, चारौली, नीम की निंबोली, करंज बीज आदि वनोपज की खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार ने इस एक्ट के तहत आदिवासी क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में स्थानीय फैसले लेने के लिए ग्रामसभाओं को सशक्त बनाने का फैसला कर लिया है। ग्रामसभाओं को कई अधिकार दिए जाएंगे। दिसंबर 2006 से पहले जमीन पर काबिज जिन आदिवासियों को पट्टे नहीं मिले हैं, उनके लिए फिर से अभियान शुरू किया जाएगा। हजारों आदिवासियों के समक्ष मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के आसपास रहने वाले जिन आदिवासी भाइयों के पास जगह की कमी होगी, उनको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत शासकीय जमीन पर भूखंड दिए जाएंगे। जगह कम पड़ी तो निजी जमीन खरीदकर भी देंगे। आदिवासी और शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय विभागों में बैकलाग के एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। सबको नौकरी नहीं मिल सकती इसलिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। इस योजना में

सीएम की घोषणाएं

- » पेसा एक्ट लागू, जनजातीय गांवों में फैसले लेने के लिए ग्रामसभा को मजबूत बनाएगी सरकार।
- » फिर शुरू होगा पट्टे बांटने का अभियान।
- » शासकीय विभागों में बैकलाग के एक लाख पदों पर होगी भर्ती।
- » बिना लाइसेंस वाले सूदखोर नहीं वसूल सकेंगे कर्ज।
- » सूदखोरों ने गरीबों को परेशान किया तो जाएंगे जेल।
- » आदिवासियों के हाथों बनी परंपरागत शराब हैरिटेज शराब के नाम से बेचेंगे।।
- » पीएम आवास योजना में घर बनाने के लिए मुफ्त में देंगे रेत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप शहीदों के स्मारक बनाए जाएंगे।
- » पातालपानी में 4.55 करोड़ की लागत से नवतीर्थ स्थल बनाया जाएगा।
- » यहां जनजातीय म्यूजियम व जननायक टंट्या मामा वाटिका भी बनेगी।

कृषि मंत्री ने किए नर्मदा मैया के दर्शन

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने मां नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर में शनिश्चरी अमावस्या के पावन पर्व पर नर्मदा मैया के दर्शन किए। मंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

ग्वालियर में पशुपालन को बढ़ावा, पहले किसान क्रेडिट कार्ड है तो बढ़ जाएगी लिमिट

पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने शुरू हुआ केसीसी अभियान

दिव्या मिश्रा, ग्वालियर।

पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग, दुग्ध संघ एवं बैंकों के समन्वय से पशुपालन गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान का आयोजन जिला स्तर पर हर शुक्रवार को उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी कार्यालय में किया जा रहा है। आगामी तीन माह तक लगातार यह शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इसके अलावा उन्हें पशुपालन से संबंधित गतिविधियों को जोड़कर आय में वृद्धि करना है। जिले के दुग्ध उत्पादक किसान पशुपालकों को मार्केटिंग, पशुचारा, पशु आहार, पशुओं का रख-रखाव एवं अन्य संसाधनों पर व्यय की पूर्ति करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में प्राप्त ऋण की राशि से पशुपालक अपने पशुधन का प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकेंगे। जिससे पशुपालक अपनी आय पांच वर्ष में दोगुनी कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में दुधारू गाय पर 15 हजार एवं दुधारू भैंस पर 18 हजार के मान से अधिकतम एक लाख 60 हजार बिना गारंटी के क्रेडिट कार्ड पर दुग्ध उत्पादक किसान पशुपालकों को दिए जाएंगे। भू-स्वामी होने की वजह से जिन किसानों के पास पूर्व से ही किसान क्रेडिट कार्ड हैं, वे अपने कार्ड पर प्रदाय राशि की लिमिट बढ़वा सकते हैं।

भूमिहीन पशुपालकों का भी बन सकता है कार्ड

साथ ही भूमिहीन पशुपालक भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। पशुपालन विभाग की निकटतम पशु चिकित्सा संस्था से संपर्क कर किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। पशुपालक द्वारा पूर्णत: भरा हुआ आवेदन निकटतम पशु चिकित्सा संस्था पर जमा किया जाना है। पशु चिकित्सा संस्था द्वारा समस्त आवेदन जिला स्तर पर आयोजित अभियान में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक आवेदनों को विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों को स्वीकृति के लिए देंगे। जिला समन्वयक संबंधित बैंक शाखा से उक्त आवेदनों पर कार्रवाई के बाद किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश में गोचर की भूमि देने से पहले अब लेनी होगी अनुमति

मुख्यमंत्री ने गोचर की भूमि के संबंध में अफसरों को दिए निर्देश

संवाददाता, भोपाल।

मध्यप्रदेश में अब गोचर के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी सरकारी भूमि को अब विकास परियोजना के लिए देने से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके लिए प्रस्ताव मध्य प्रदेश गौ पालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के पास जाएगा। इसकी सहमति मिलने के बाद ही भूमि आवंटन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गायों के लिए घास के मैदान आसानी से उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यदि गोचर की भूमि विकास परियोजना के लिए अति आवश्यक है तो उसे देने से पहले बोर्ड से सहमति लेनी होगी। इसके बाद ही विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी तय किया गया कि बंद किए गए आठ गौ-सदनों को फिर से प्रारंभ किए जाएंगे। जबलपुर जिले के गंगई वीर में सरकार की 530 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यहां पर गायों के लिए वन विहार बनाकर दो हजार गायों को आश्रय दिया जाएगा। बजट में गायों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रविधान भी किया है।

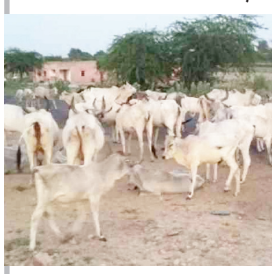

भेजे जा रहे हैं प्रचार रथ, कृषि विभाग के अफसर बताएंगे फायदे

फसल बीमा का लाभ बताने गांव गांव में लगेगी किसान चौपाल

संवाददाता, भोपाल।

किसानों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा अधिक से अधिक कराया जाएगा। इसके लिए सरकार पहली बार मध्यप्रदेश में किसान चौपाल लगाने जा रही है। पांच हजार जगहों पर यह चौपाल लगेगी। इसमें कृषि और फसल बीमा करने वाले कंपनियों के प्रतिनिधि किसानों को फसल बीमा कराने के फायदे बताएंगे। इस दौरान वे किसान अपने अनुभव भी साझा करेंगे, जिन्हें फसल बीमा का लाभ मिला है। मध्य प्रदेश में रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक होना है। सहकारी बैंकों से अल्पावधि ऋण वाले किसानों का प्रीमियम काटकर बैंक बीमा करा लेते हैं लेकिन अऋणी किसानों की इसमें रुचि कम रहती है।

पिछले साल जब खरीफ फसलें अतिवर्षा से प्रभावित हुई थीं, तब सरकार ने केंद्र सरकार की विशेष अनुमति से अभियान चलाकर फसल बीमा कराया था। किसानों से प्रीमियम जमा कराने के लिए रविवार को भी बैंकों की शाखाएं खुलवाई गई थीं। इसका फायदा यह हुआ था कि बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 40 लाख तक पहुंच गई थी। इसे देखते हुए अब कृषि विभाग ने तय किया है कि किसानों को फसल बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गांवों में चौपाल लगाई जाएंगी। इसके लिए प्रचार रथ भी गांव-गांव भेजे जा रहे हैं।

पांच हजार करोड़ मिलेगा बीमा

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले खरीफ सीजन में अतिवर्षा से प्रभावित फसलों का बीमा किसानों को जल्द मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। संभावना है कि पांच हजार करोड़ तक बीमा किसानों को मिल सकता है। इसके पहले खरीफ 2018 में नौ लाख 51 हजार किसानों को एक हजार 987 करोड़, रबी 2018-19 में दस लाख 42 हजार किसानों को एक हजार 372 करोड़, खरीफ 2019 में 24 लाख 49 हजार किसानों को पांच हजार 799 करोड़ और रबी 2019-20 में 96 हजार 824 किसानों को 53.62 करोड़ रुपए का फसल बीमा मिल चुका है।

2019 में 2.6 लाख को मिला था लाभ

गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2019 में केंद्र सरकार के पोर्टल में प्रविष्टि नहीं हो पाने के कारण दो लाख 64 हजार किसानों को बीमा नहीं मिल पाया था। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष अनुरोध करके पोर्टल खुलवाकर प्रविष्टि कराई है। इससे किसानों को 384 करोड़ रुपए का फसल बीमा मिलेगा।

कृषि विभाग किसानों से पूसा तेजस (8656) प्रजाति के गेहूं की खेती पहली बार करा रहा है

पूसा तेजस का उत्पादन किसानों का कर देगा मालामाल

रतलाम।

जिले में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने व गुड प्रैक्टिस अपनाने के लिए कृषि विभाग किसानों से पूसा तेजस (8656) प्रजाति के गेहूं की खेती पहली बार करा रहा है। विभाग का दावा है कि इससे प्रति हेक्टेयर 25 क्विंटल तक उत्पादन बढ़ेगा और भाव भी अच्छे मिलेंगे। इस गेहूं का खाने के साथ सर्वाधिक दलिया, पास्ता और ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। जिले के हर विकास खंड में पहली बार 25-25 हेक्टेयर में पूसा तेजस की खेती की गई है। एक हेक्टेयर या इससे अधिक रकबे में 125 किसानों ने नई किस्म को अपनाया। इसके लिए ब्लाकवार छह कलस्टर बनाए गए हैं और एक कलस्टर में 25 हेक्टेयर का रकबा शामिल कर किसानों को प्रेरित किया गया। ग्राम बीज योजना, सामान्य बीज वितरण अनुदान पर या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में फसल पद्धति के माध्यम से अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा किसानों को बोवनी के पहले प्रशिक्षण भी दिया गया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप संचालक विजय चौरसिया ने बताया कि कृषि अनुसंधान केंद्र से प्रमाणित बीज प्राप्त कर किसानों को उपलब्ध कराया गया है। इंदौर जिले में इस प्रजाति की खेती से किसान प्रति हेक्टेयर 90 क्विंटल तक उत्पादन ले रहे हैं। इस गेहूं की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा भाव भी मिल रहा है। रतलाम जिले में भी परिस्थितियां अनुकूल हैं। यहां अच्छा उत्पादन मिलेगा। प्रयोग यदि सफल रहा तो अगले साल से रकबा बढ़ा देंगे। वर्तमान में यहां 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। पूसा तेजस से अब 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा।

एक नजर में पूसा तेजस किस्म

खेती का रकबा 150 हेक्टेयर, जिले में कुल छह क्लस्टर, एक क्लस्टर में 25 हेक्टेयर, खेती करने वाले कुल किसान 125, वर्तमान में उत्पादन 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, पूसा तेजस से बढ़कर हो जाएगा 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।

सबसे बड़ी कृषि विश्वविद्यालय की एक्सपर्ट की राय

चने की फसल को इल्लियों से बचाएगा गेंदे का फूल

भोपाल। मध्यप्रदेश का चना पूरे देश में प्रसिद्ध है। देश में सबसे अधिक चने की प्रजाति इसी प्रदेश में बोई जाती है। जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर ने मप्र के लिए 30 किस्में विकसित की है। कई किसान इसकी दो फसल काटते हैं। किसानों के सामने उकठा रोग और इल्लियों के प्रभाव से चने की फसल बचाने की बड़ी चुनौती रहती है। समय पर ध्यान नहीं दें तो किसान का सारा परिश्रम बेकार चला जाता है। अधिकतर किसान चने की बोवनी कर चुके हैं। अब फसलों की देखभाल की चुनौती है। **'जागत गांव हमार'** अपने इस अंक में किसानों के लिए लेकर आया है जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर की प्रमुख वैज्ञानिक एवं एक्सपर्ट अनीता बब्बर द्वारा बताए गए चने की अच्छी फसल लेने के तरीके।

दो सिंचाई होता है अच्छा उत्पादन

एक्सपर्ट अनीता बब्बर के अनुसार चने की फसल 110 से 120 दिन में तैयार होती है। चना कम सिंचाई वाली फसल है। बोवनी से 45 दिन के अंदर पहली सिंचाई करनी पड़ती है। वहीं दूसरी सिंचाई दाना भरने के बाद करनी चाहिए। मतलब बोवनी के 75 दिनों पर करनी चाहिए। खरपतवार एक बड़ी समस्या होती है। इससे बचाने के लिए पेंडी मेथालीन 350 ग्राम 350 लीटर पानी में घोल बनाकर एक एकड़ में कर सकते हैं। पहली निराई-गुड़ाई बोवनी के 35 दिनों बाद और दूसरी 60 दिनों बाद आवश्यकतानुसार करना चाहिए।

उकठा रोग से बचाना जरूरी

चने के प्रमुख रोगों में उकठा रोग मुख्य है। फसल की बोवनी के 30 दिन बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं। जड़ में काली धारी दिखे या फिर फसल पीलेपन लिए झुक जाएं तो समझ लें कि उकठा रोग लग गया है। यह रोग जड़, तना में होता है। यदि किसान ने जेजी-12 या जेजी-36 लगाई हो तो उसे चिंता करने की बात नहीं है। दोनों किस्में रोगरहित हैं। उकठा रोग से फसल प्रभावित दिखे तो हल्की सिंचाई के बाद ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास का छिड़काव कर दें। जमीन गिली होने से इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा।

» फसल को उकठा रोग से बचाने ट्राइकोडर्मा छिडकें

» चने के बीज की नई जेजी-24 प्रजाति विकसित

» अगले साल से आम किसानों को मिलेगा बीज

झुलसा रोग से बचाएं

अल्टरनेरिया झुलसा रोग भी चने की पैदावार को 50 प्रतिशत तक प्रभावित कर सकते हैं। यह रोग फूल या फली बनते समय लगता है। इसमें पत्तियों पर छोटे, गोल-बैंगनी धब्बे बनते हैं। यह नमी अधिक होने से पूरी पत्ती पर फैल जाता है। नियंत्रण के लिए 03 ग्राम मैंकोजेब, 75 प्रतिशत डब्ल्यूपी या दो ग्राम मेटालैक्सिल 8 प्रतिशत मैंकोजेब 64 प्रतिशत लीटर पानी में छिड़काव कर दें।

बीच में करें धनिया की बोवनी

चने में इल्लियों का प्रभाव फल आने पर दिखने लगता है। यदि किसान ने बोवनी के समय ही आईपीएम विधियां अपनाएं हैं, तो इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं। इसमें चने की हर 10 क्यारी के बाद एक से दो क्यारी धनिया की बोवनी करनी चाहिए। धनिया की महक से इल्लियां दूर

टी-आकार की खूंटी लगा दें

किसान खेत के चारों ओर मेड़ पर हाईब्रिड गेंदे का फूल लगा दें। इससे इल्लियां चने की बजाए फूल पर ही अंडा देंगी और फसल बच जाएगी। यदि एक वर्गमीटर में एक से दो इल्ली दिख रहे हैं तो एक एकड़ में 30 से 40 टी-आकार की खूंटी लगा दें। इससे चिड़िया इस पर बैठेंगी और इल्लियों को खा लेंगी। ये भी प्रभावी उपाय है।

अनीता बब्बर, मुख्य वैज्ञानिक, चना परियोजना, कृषि विवि, जबलपुर

हार्वेस्टर से काटेगी चन की फसल

गेहूं-धान की तरह चने की फसल भी हार्वेस्टर से काटने की सुविधा हो तो कितनी अच्छी हो जाए। किसान भी यही सोचते होंगे, लेकिन मजबूरी ये कि चने का पौधा आकार में छोटा और फलियां नीचे की ओर लटक कर फलती हैं। लेकिन, अब जबलपुर के जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि के वैज्ञानिकों ने ये कमाल कर दिखाया है। उन्होंने चने के बीज की ऐसी प्रजाति जीजे-24 विकसित की है, जिसका पौधा गेहूं-धान की तरह 65 से 70 सेमी ऊंचाई का होता है। विवि में चना परियोजना की मुख्य वैज्ञानिक के मुताबिक ये प्रजाति 2020 में विकसित की गई थी। इस बार इसका बीज तैयार किया जा रहा है। अगले वर्ष आम किसानों को इसका बीज मिलेगा।

इनका कहना है

इस चने की खासियत यह है कि इसके पौधे धान-गेहूं की तरह 65 से 70 सेमी ऊंचाई वाले होते हैं। इसकी फली ऊपर की ओर लगती है। दानों का आकार भी बड़ा होता है। तना इतना मजबूत होगा कि फली अधिक लगने पर भी गिरेगा नहीं। इसे आसानी से हार्वेस्टर से किसान काट सकेंगे। मप्र चने के उत्पादन में नंबर वन है। ये प्रजाति किसानों का समय और श्रम दोनों बचाएंगे। कंबाई से चना गिरेगा नहीं। इसका बीज अगले साल उपलब्ध होगा।

फसलों को दें संतुलित खाद, अंधाधुंध उपयोग से बढ़ रही लागत

किसानों को सलाहः अधिक रासायनिक उर्वरकों का न करें उपयोग

इंदौर। किसानों को चाहिए कि वे अपनी फसलों को जितनी जरूरत हो, उतना ही खाद दें। इसके लिए अलग-अलग फसलों के लिए लगने वाले पोषक तत्वों का ध्यान रखते हुए ही खाद और उसकी मात्रा का चयन करें। कई किसान बिना सोचे-समझे रासायनिक खाद का बेतहाशा उपयोग कर रहे हैं। इससे न केवल खेती की लागत बढ़ रही है, बल्कि जमीन में जरूरत न होने के बावजूद एक ही तरह के तत्वों की भरमार हो रही है। कृषि विभाग ने किसानों को यह सलाह दी है। संयुक्त संचालक कृषि ने किसानों को सलाह दी है कि आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करें। फसल के लिए अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि किसान मिट्टी परीक्षण

कराएं। फिर उसी के हिसाब से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाए। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे कृषि वैज्ञानिकों से पूरी जानकारी प्राप्त कर उर्वरकों का उपयोग करें ताकि फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। वर्तमान मे रबी की फसलों के लिए जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। गेहूं के लिए यूरिया 213 किलोग्राम, एनपीके 186 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चना के लिए यूरिया 44 तथा सुपर फास्फेद 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सरसों के लिए यूरिया 130 किलो, सुपर फास्फेट 188 किलो तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मसूर के लिए यूरिया 54 किलो तथा सुपर फास्फेट 313 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देकर अनुशंसित उर्वरक मात्रा की पूर्ति की जा सकती है। किसान भाइयों से अपील है कि गेहूं, सरसों, चना एवं मसूर फसल में रासायनिक खाद की अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करें। डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके व एसएसपी यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरकों का उपयोग कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग

मप्र देश की सर्वाधिक गौवंश और गौशालाओं वाला प्रदेश

गौ संवर्धन के मामले मध्य प्रदेश सरकार अच्छा कार्य कर रही है। वर्तमान में मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक गौवंश और गौशालाओं वाला प्रदेश है। यहां गौवंश के विकास, गौ-पालन, गौ-संरक्षण, गौ-संवर्धन और गौ आधारित उत्पादों के संवर्धन के लिये सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना और अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित 1768 गौ-शालाओं में ढाई लाख से ज्यादा गौ-वंश की देखभाल की जा रही है। शासन द्वारा प्रति गौवंश प्रति दिवस के मान से 20 रुपये का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना में अब तक पूर्ण 1141 गौ-शालाओं में 76 हजार 941 गौ-वंश का पालन किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं की पंजीकृत 627 गौ-शालाओं में भी करीब एक लाख 74 हजार गौ-वंश की देखभाल की जा रही है।

विकसित होंगे गौवंश वन्य विहार

गौ-वंश को जंगल से आहार और वन को गोबर से खाद मिलने की व्यवस्था प्राकृतिक है। गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा जंगलों के पास गौ-वंश वन्य विहार विकसित किये जा रहे हैं। रीवा जिले के बसावन मामा क्षेत्र में 51 एकड़ क्षेत्र में गौ-वंश वन्य विहार विकसित किया गया है, जिसमें 4 हजार गौ-वंश हैं। जबलपुर जिले के गंगईवीर में 10 हजार और दमोह जिले में 4 हजार गौ-वंश की क्षमता वाला वन्य विहार विकसित किया जा रहा है। आगर-मालवा के सुसनेर में 400 एकड़ में कामधेनु अभयारण्य विकसित किया गया है, जिसमें वर्तमान में 3400 बेसहारा, वृद्ध और बीमार गायों की देखभाल की जा रही है। इसी माह सागर विश्वविद्यालय में कामधेनु पीठ की स्थापना भी की गई है।

मध्यप्रदेश में गौ हत्या संज्ञेय अपराध

प्रदेश में गौ हत्या संज्ञेय अपराध है। यहां आरोप सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान है। मप्र में चार प्रजाति का देशी गौ-वंश पाया जाता है, जिनका दूध गिर गाय की तरह ही स्वर्णयुक्त एवं उच्च गुणवत्ता वाला है। देशी गाय के दूध में मानव स्वास्थ्य के लिये आवश्यक सभी पोषक तत्व पाये जाते हैं।

प्रतिदिन 9.13 लाख किलो ली. दूध का संकलन

प्रदेश में लगभग सवा 7 हजार दुग्ध सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से पिछले वित्त वषज़ में प्रतिदिन औसतन 9 लाख 13 हजार किलो लीटर दुग्ध संकलन और औसत 6 लाख 38 हजार लीटर पैकेट दुग्ध विक्रय हुआ है। लॉकडाउन के दौरान दुग्ध संघों द्वारा 2 करोड़ 54 लाख लीटर दूध अतिरिक्त रूप से खरीदा गया। उल्लेखनीय यह भी है कि कोरोना लॉकडाउन के कारण जहां कई व्यवसाइयों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, वहीं दुग्ध उत्पादक किसानों को 94 करोड़ रुपये राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

आइसक्रीम, पनीर आदि संयंत्रों का निर्माण

पिछले एक साल में इंदौर में 4 करोड़ रुपये की लागत से आइसक्रीम संयंत्र और खण्डवा में 25 हजार लीटर क्षमता के संयंत्र निर्माण का कार्य पूरा हुआ। जबलपुर में पौने 10 करोड़ रुपये की लागत से 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित पनीर निर्माण संयंत्र की स्थापना का काम भी पूरा हो चुका है। सागर में भी एक लाख लीटर क्षमता के संयंत्र की स्थापना की गई।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा

दुग्ध संयंत्रों को ऊर्जा में आत्म-निर्भर बनाने के लिये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के 5 संयंत्रों में 4 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से सौर ऊर्जा आधारित गर्म पानी के संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

अतिरिक्त दूध से बन रहा मिल्क पावडर

दुग्ध संघों द्वारा वितरण से बचे हुए दूध का मिल्क पावडर बनाकर महिला-बाल विकास विभाग की टेक होम राशन योजना के लिये प्रदाय किया जाता है। आंगनवाड़ियों के लिये सुगंधित मीठा दुग्ध चूर्ण भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है।

16 लाख किसान क्रेडिट-कार्ड वितरण कार्यक्रम

बैंकों द्वारा पशुपालन गतिविधियों के लिये 83 हजार 903 नवीन किसान क्रेडिट-कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई हैं। दुग्ध सहकारी समितियों से संबद्ध पशुपालकों के लगभग 4 लाख आवेदन विभिन्न बैंकों में प्रस्तुत किये गये हैं। साथ ही केन्द्र शासन द्वारा 15 नवम्बर, 2021 से 15 फरवरी, 2022 तक चलने वाले केसीसी अभियान में प्रदेश के 16 लाख पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य निधार्रित है। दुग्ध उत्पादक किसानों को 2 लाख रुपये की सीमा तक इलाज के लिये साँची आरोग्य चिकित्सा सहायता योजना शुरू की गई है।

देश की दूसरी सीमन प्रयोगशाला भोपाल में

केन्द्रीय वीर्य संस्थान द्वारा साढ़े 47 करोड़ रुपये की लागत से देश की दूसरी सेक्स सार्टेड सीमन प्रयोगशाला भोपाल में स्थापित की गई है। प्रयोगशाला में अब तक 21 हजार 580 सीमन का उत्पादन किया जा चुका है। सागर जिले के रतौना में राष्ट्रीय गोकुल मिशन में गोकुल ग्राम और कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र विकास योजना में दतिया जिले के नौनेर में आत्म-निर्भर मप्र के तहत प्रदेश का दूसरा वीर्य उत्पादन संस्थान स्थापित किया गया है। पिछले साल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 1500 और गोकुल मिशन में 850 मैत्री को प्रशिक्षण दिया गया।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये टीकाकरण

प्रदेश के सभी गौ-भैंस वंशीय पशुओं को नेशनल एनीमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में एफएमडी और ब्रूसेल्ला का टीका लगाया गया। समस्त पशुओं को यूआईडी टेग लगाकर इनाफ पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में ढाई करोड़ से अधिक पशुओं का एफएमडी रोग के विरुद्ध टीकाकरण किया गया है। उद्देश्य वर्ष 2025 तक मुँहपका, खुरपका (एफएमडी) और ब्रूसेल्ला रोग पर नियंत्रण पाना और वर्ष 2030 तक इनका उन्मूलन करना है। दुधारु पशुओं के निरोगी होने से दूध, पशुधन और उत्पादों में वृद्धि होगी।

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

कार्यक्रम के प्रथम चरण में 7 लाख 65 हजार गौ-भैंस वंशीय पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, 5 लाख 91 हजार गर्भधारण परीक्षण और एक लाख 62 हजार वत्सोत्पादन किया गया। द्वितीय चरण में 19 लाख 15 हजार गौ-भैंस वंशीय पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, 9 लाख 29 हजार का गर्भधारण परीक्षण और 38 हजार 365 वत्सोत्पादन हुआ। तीसरा चरण एक अगस्त, 2021 से प्रारंभ होकर 31 मई, 2022 तक चलेगा। इसमें अब तक डेढ़ लाख कृत्रिम गर्भाधान और 3 हजार से अधिक गर्भ परीक्षण किये जा चुके हैं। इनकी प्रविष्टि भी इनाफ पोर्टल पर की जा रही है।

बकरी दूध विक्रय आरंभ

जनजातीय गौरव दिवस से प्रदेश में ग्राहकों को बकरी का दूध भी मिलना आरंभ हो गया है। बकरी दूध विक्रय की शुरूआत जनजातीय बहुल जिलों सिवनी, बालाघाट और धार, झाबुआ और बड़वानी जिलों में उत्पादित 50 से 70 रूपये प्रतिकिलो की दर से खरीदे गये दूध से की गई है।

सुनीता दुबे, मप्र में जनसंपर्क अधिकारी

देश को ऊर्जा साक्षरता का पाठ पढ़ायेगा मध्यप्रदेश

देश और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु असंतुलन और बिजली के अपव्यय से बचाने के लिये ऊर्जा साक्षरता अभियान (ऊषा) के रूप में लोगों को जागरूक करने की अनूठी पहल मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने की है। अभियान में प्रदेश के साढ़े 7 करोड़ नागरिकों को समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर ऊर्जा साक्षर बनाने के प्रयास किये जायेंगे। पहले 6 महीनों में 50 लाख नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने का लक्ष्य है।

ऊर्जा साक्षरता अभियान: अभियान का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा प्रयोग के प्रति संवेदनशील बनाते हुए आगामी वर्षों में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संतुलन के दुष्प्रभावों से बचाना है। इसके अंतर्गत ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय की समझ विकसित करना, ऊर्जा के पारम्परिक एवं वैकल्पिक साधनों की जानकारी देना, उनका पर्यावरण पर प्रभाव, ऊर्जा एवं ऊर्जा के उपयोग के बारे में सार्थक संवाद, ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में जागरूकता, ऊर्जा उपयोग के प्रभावों, परिणामों की समझ के आधार पर इसके दक्ष उपयोग के लिये निर्णय लेने की दक्षता उत्पन्न करना, पर्यावरणीय जोखिम एवं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना और विभिन्न ऊर्जा तकनीकों के चयन के लिये लोगों को सक्षम बनाया जायेगा। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों सहित जन-साधारण को ऊर्जा की महत्ता, पारम्परिक ऊर्जा से होने वाला कार्बन उत्सर्जन, सौर, पवन, बॉयोमॉस आदि हरित ऊर्जा के लाभ और मितव्ययता आदि की विस्तृत जानकारी दी जायेगी। अभियान के जरिये लोगों को बताया जायेगा कि एक यूनिट बिजली बचाने से लगभग 2 यूनिट बिजली का उत्पादन बढ़ता है।

नई पीढ़ी द्वारा ऊर्जा निर्माण और सदुपयोग में जागरूकता के दूरगामी परिणाम होंगे। ऊर्जा उपयोग के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ की जानकारी सुलभ रूप में पहुँचाने और अपनाने का कार्य मिशन के रूप में किया जायेगा। श्रेणीगत प्रशिक्षण के माध्यम से चरण-बद्ध सर्टिफिकेशन का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी नागरिकों को समयबद्ध कार्य-योजना के अनुसार ऊर्जा साक्षर बनाया जायेगा। पोस्टर, होर्डिंग, एनीमेशन, वीडियो, सोशल मीडिया, जिंगल्स, मोबाइल एप, स्वयं करके देखो आदि विधाओं द्वारा रोचक तरीके से लोगों को क्लीन ऊर्जा के संवर्धन और संरक्षण के लिये प्रेरित किया जायेगा।

मोबाइल से होगा पंजीयन: ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ना पूरी तरह नि:शुल्क है। वेब पोर्टल या मोबाइल एप से एप डाउनलोड कर मोबाइल ओटीपी के माध्यम से पंजीयन होगा। इसके बाद लोग अपनी इच्छानुसार निर्धारित पाठ्यक्रमों में से एक का चयन कर सकेंगे। पाठ्यक्रम के चयन पर प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम (मॉड्यूल) डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। प्रतिभागी अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन पद्धति से बहु-विकल्पीय प्रश्नों के रूप में एक परीक्षा में भाग ले सकेगा।

जैविक कृषि उत्पाद: विपणन की होड़, उत्पादन में अरुचि

देश में आज बेरोजगारी की विकराल समस्या मुंह बाए खड़ी है। युवाओं के लिये रोजगार सबसे बडी चुनौती देखने को मिल रही है। इस बेरोजगारी में सबका ध्यान कृषि क्षेत्र की तरफ आने लगा है, जो लोग अपनी कृषि योग्य भूमि छोड़ कर पलायन कर चुके थे अब धीरे-धीरे वापस आने लगे हैं।

परन्तु अब गौर करने वाली यह है इस कोविड के काल में कृषि क्षेत्र के उत्पादन की ओर युवा वर्ग का ध्यान तो जा रहा है, लेकिन सिर्फ उत्पाद विपणन की ओर, क्योंकि उन युवा लोगों ने सुना है या इन्टरनेट शिक्षा के तहत जानकारी हासिल कर ली है कि कृषि में जैविक बाजार की मांग आसमान छू रही है। इसलिए युवा वर्ग ने अपना लक्ष्य जैविक उत्पादों के विपणन में बना दिया है, कई ऐसे लोग भी इस बाजार में आ चुकें है जिनकों कृषि का ज्ञान शून्य के बराबर है। स्थानीय उत्पादों की कोई जानकारी नहीं है कृषि तकनीकि का भी ज्ञान नहीं है और ना ही उत्पादों के रचना के बारें में जानकारी रखते हैं बस विपणन की होड़ में बहे जा रहे हैं।

कोरोना के दौर में किसानों की समस्याएं तथा उनके उपाय सिर्फ लघु अवधि मे पैसा कमाना उद्देश्य हो गया है और जैविक उत्पादों के नाम पर उपभोक्ता को लूटना। इस जैविक की लूट के दौर में ऐसे उपभोक्ता को शिकार होना पड़ रहा है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हैं, क्योंकि शुद्ध एवं रसायनमुक्त उत्पादों का सेवन सभी करना चाहते हैं, लेकिन पूंजीपती लोगों तक ही जैविक उत्पादों की पहुंच हो रही है। गरीब एवं आम जनमानस के स्वास्थ के विषय में कोई नहीं सोच रहा है कि वह लोग भी रसायनमुक्त अनाज खायें उनके लिए सिर्फ राशन की दुकानों का गेंहू चावल, चना वितरण किया जा रहा है। यदि इस पर कोई कार्य करने की सोचें, तो बदलाव की संभावना हों पायेगी कि आम जन तक जैविक, शुद्ध एवं रसायनमुक्त अनाज उपलब्ध हो पायें। कुर्सी और टेबल का सहारा लेकर विपणन सम्बन्धी बैठक करना लेवल, पैकिंग, ब्रान्डिंग की चर्चाएं सब कर रहें है, लेकिन उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय यह कोई नहीं कर रहा है। मैने स्वयं बड़ी बड़ी सेमिनारों में सुना है कि विपणन की प्रकिया ऐसी होगी इतना मिट्रिक टन विपणन किया जायेगा, परन्तु विपणन होगा कहां से जब उत्पादन ही नहीं होगा अन्यथा जो युवा वर्ग सिर्फ इस प्रकार के विपणन की बात करते हैं। कहीं उनका पुराना व्यवसाय या लगा लगाया व्यवसाय छूट ना जाये।

अभी मुरैना शहर में पाली जा रही 19000 से ज्यादा भैंसे

नगर निगम अनुबंध के बाद भी नहीं बना रहा गोबर से खाद

» जिले में हर रोज निकलता है 45 से 50 टन तक गोबर

» बस स्टैंड के पास जैविक खाद का प्लांट भी हो गया बंद

अवधेश डंडोतिया, मुरैना।

मुरैना शहर में कूड़ा-कचरे के साथ निकल रहा गोबर, स्वच्छता अभियान एवं नगर निगम की फजीहत कर रहा है। कोई भी सफाई कंपनी शहर की स्वच्छता का ठेका लेने तक तैयार नहीं होती। मुसीबत बन चुके गोबर को नगर निगम ने कमाई का जरिया बनाने की योजना बनाई, इस पर लाखों रुपये खर्च भी कर दिए, पर गोबर से एक रुपए की आमदनी नहीं हो पाई। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार मुरैना शहर में 19000 से ज्यादा भैंसे पाली जा रही हैं। शहर के कॉलोनी, मोहल्लों की सड़कों से लेकर पार्कों तक में यह भैंसें बांधी जा रही है। इन भैंसों से इतना गोबर निकलता है कि, रोज सुबह सड़कों किनारे से गोबर को उठाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा डंपर व ट्रैक्टर-ट्रॉली, मिनी जेसीबी लगाई जाती है। निगम के रिकॉर्ड अनुसार शहर में हर रोज 92 से 94 टन कचरा निकलता है, इसमें से 45 से 50 टन गोबर होता है। इस गोबर के कारण अधिकांश नाले-नालियां चोक हो गए हैं।

डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन जाने वाले वाहनों में कचरे से ज्यादा गोबर भर दिया जाता है। इसी गोबर से केंचुआ पद्धति से जैविक खाद बनाने के लिए नगर निगम ने चंबल एग्रो फार्मर प्रॉड्यूसर कंपनी से अनुबंध किया, जिसके तहत गोबर से बनने वाले खाद को चंबल एग्रो फार्मर प्रॉड्यूसर कंपनी खरीदेगी। निगम प्रशासन ने 20 फरवरी को देवरी में गोबर से खाद बनाने का प्लांट शुरू, लेकिन यह काम परवान नहीं चढ़ सका। इसी तरह पुराने बस स्टैंड पर जैविक खाद का प्लांट बनाया गया, जो बंद पड़ा है।

मिलावटी दूध ने बढ़ाई भैंस

मुरैना जिले में मिलावटी व नकली दूध का डर ऐसा है, कि अधिकांश लोग डेयरियों से दूध खरीदने में डरते हैं। बस इसी डर ने शहर में भैसों की संख्या बढ़ा दी है। नकली व मिलावटी दूध से बचने के लिए लोग अपने आस-पास ही पल रही किसी भैंस का दूध खरीदते हैं। मिलावट के इस डर से हजारों परिवारों को रोजगार दिया है और लोगों को शुद्ध दूध आलम यह है कि गली-मोहल्ले या पार्क तो छोड़िए टूलेन सड़कों के डिवाइडरों किनारे भैंस बांधकर पाली जा रही हैं। जिस डिवाइडर में पौधे उगने थे वह मवेशी के चारे के खनेटा बना दिया है।

इनका कहना है

गोबर से जैविक खाद बनाने का काम 6 टैंकों में शुरू कर दिया गया है। इसे और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि शहर में जितना कचरा निकल रहा है उसमें से आधी मात्रा गोबर की है। गोबर के कारण नाले-नालियां भी चोक हो रही हैं।

संजीव कुमार जैन, कमिश्नर, नगर निगम मुरैना

-उज्जैन जिले में यूरिया संकट बरकरार

दावों पर भारी यूरिया संकट

संवाददाता, उज्जैन।

सरकार के लाख जतन के बाद भी जिले में यूरिया संकट बरकरार है। हालांकि 2600 टन का रैक आने का अफसर कह रहे हैं। इसमें से भी 1800 टन उज्जैन जिले को मिलेगा। 800 टन शाजापुर भेजा जाएगा। टुकड़े-टुकड़े में आ रहा यूरिया किसान व सोसायटियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यूरिया की कमी के चलते गेहूं के उत्पादन पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। सरकार भले ही यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था करने का दावा कर रही है हो, हकीकत में इस बार यूरिया की काफी कमी दिखाई दे रही है।

किसान को गेहूं की चमक व उत्पादन कमजोर होता दिखाई दे रहा है। समय पर खाद न मिलने पर फसल का उत्पादन प्रभावित होना तय है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 4.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की बोवनी हुई है। जिसमे 3.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोवनी की है। जिनके अच्छे उत्पादन के लिए करीब 40 हजार टन यूरिया की जरूरत है। गेहूं का पौधा करीब एक माह से अधिक का हो गया है, लेकिन यूरिया की उपलब्धता मात्र 20 हजार टन की हो पाई है। डीएमओ विनय तिवारी के अनुसार इफ्को का 2600 मेट्रिक टन यूरिया का रैक आ रहा है जिसमे 1800 टन उज्जैन जिले में वितरण होगा। उनके अनुसार 1700 टन यूरिया सीधे सहकारी संस्थाओं को भेजा जा जाएगा। 100 टन कृषि मंडी स्थित मार्केटिंग संस्था व एमपी एग्रो को देंगे। इसके अलावा एक दो दिन में महिदपुर में भी 2000 टन यूरिया आ रहा है। जिसमे से 1400 टन का वितरण महिदपुर, नागदा व खाचरौद की सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होगा। इधर, किसानों का कहना है कछुआ चाल से आ रहे यूरिया से तो फसल में उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। अभी अनेक किसान सोसायटी व निजी खाद की दुकानों पर यूरिया के लिए भटक रहे हैं।

पौने चार लाख किसान वंचित

सरकारी आंकड़ों की बात करें तो जिले में करीब पौने चार लाख किसानों को यूरिया मिलना मुश्किल है, क्योंकि 172 सोसायटियां जिले में कार्यरत हैं। जिनके पंजीकृत किसानों का आंकड़ा 1 लाख 15 हजार के करीब है। वर्तमान में इन किसानों को क्रेडिट पर यूरिया मिलना है। जो कि कमी के चलते भटक रहे हैं। इधर सरकार ने अपंजीकृत 3 लाख 70 हजार किसानों को भी नकद में सोसायटियों से यूरिया मिलने की बात कही है।

-तुलाई शुरू नहीं होने से किसानों में आक्रोश

जबलपुर के खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंचे बारदाना

संवाददाता, जबलपुर।

जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए लगभग 59 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। नतीजा किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी फसल बिचौलियों को कम दाम पर बेचने मजबूर हैं। किसान बताते हैं कि सहकारी समिति बरेला, पड़वार, पिंडरई, पडरिया स्थित खरीदी केंद्रों में धान की तुलाई शुरू नहीं हुई है। कुछ केंद्रों में बारदाना तक नहीं पहुंच पाए हैं। सहकारी समिति बरेला अंतर्गत धान खरीदी के लिए दो केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से पहला केंद्र महंगवा रोड स्थित राय वेयर हाउस और दूसरा केंद्र बिलहरी रोड स्थित वेयर हाउस में बनाया गया है। अभी तक केवल एक केंद्र में ही तुलाई प्रारंभ हो सकी है और दूसरे केंद्र में तुलाई का कोई अता-पता नहीं है।सहकारी समिति पड़रिया अंतर्गत धान खरीदी के लिए अफजल वेयर हाउस कैलवास और सगड़ा स्थित वेयर हाउस में दो खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। प्रभारी समिति प्रबंधक सतीश अवस्थी ने बताया कि अभी तक खरीदी केंद्रों में कोई बारदाना नहीं आया है। इसलिए अब तक तुलाई प्रारंभ नहीं हो सकी है। खरीदी केंद्रों पर गत वर्ष लगभग 47000 क्विंटल धान खरीदी की गई थी। समय पर खरीदी प्रारंभ न होने से क्षेत्रीय किसान परेशान हैं।

केंद्रों में नहीं व्यवस्था

सहकारी समिति पड़वार अंतर्गत पुरवा स्थित ठाकुर वेयर हाउस तथा कल्याणपुर स्थित वेयर हाउस में खरीद केंद्र बनाए गए हैं। दोनों केंद्रों में औपचारिकता के तौर पर तुलाई तो प्रारंभ हो गई, लेकिन केंद्रों में किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सहकारी समिति पड़रिया द्वारा मारुति वेयर हाउस में खरीदी केंद्र बनाया गया है। अभी तक विपणन संघ द्वारा इस केंद्र में बारदाना तक नहीं पहुंचाए गए हैं। प्रभारी समिति प्रबंधक संजय विश्वकर्मा का कहना है कि बारदाना आने पर तुलाई प्रारंभ हो जाएगी।

मप्र के पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का सफल प्रयास, भोपाल के बुल मदर फार्म में सेरोगेसी से जन्मी 298 गाय मौजूद

2 ली.दूध देने वाली गाय की बछिया दे रही 15-20 ली. दूध

संवाददाता, भोपाल।

देशी गायों के संरक्षण एवं उनमें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं।

ऐसा ही एक फार्म मध्यप्रदेश के पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा वर्ष 2014-15 में भोपाल में शुरू किया गया था। भोपाल के केरवा स्थित मदर बुल फार्म पर भ्रूण प्रत्यारोपण के बहुत अच्छे परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। सर्वोत्तम गिर नस्ल की गाय और सांड से आरंभ किये गये इस प्रोजेक्ट से आज फार्म पर सेरोगेसी से जन्मी 298 गाय मौजूद हैं, जिन्सें उच्च गुणवत्ता का दूध प्राप्त किया जा रहा है।

तेजी से बढ रही है गायों की संख्या

वर्तमान में बुल मदर फार्म पर 386 देशी गाय हैं। देश की सर्वाधिक दूध देने वाली गिर, थारपरकर और साहीवाल नस्ल की इन गायों से उच्च गुणवत्ता का दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ही गायों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 6 साल पहले गिर नस्ल के जोड़े से 15 गायों के साथ शुरू किये गये प्रयोग में वर्ष 2015-16 में 7 बछड़े और 8 बछियों के जन्म के साथ सफलता का क्रम आज भी जारी है।

डॉ. एच.बी.एस. भदौरिया, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

निरंतर बढ़ रही है गुणवत्तापूर्ण अधिक दूध देने वाली देशी गायों की संख्या

2 लीटर तक दूध देने वाली देसी गाय में प्रत्यारोपित भ्रूण से जन्मी बछिया आज 15 से 20 लीटर दूध प्रतिदिन दे रही है। गिर और साहीवाल नस्ल की गाय 15 से 20 लीटर और थारपरकर नस्ल की गाय 10 से 20 लीटर प्रतिदिन दूध दे रही हैं। एक गाय अपने जीवनकाल में केवल 7 से 8 बार गर्भ धारण करती है। इसके विपरीत सेरोगेसी तकनीक से सर्वोत्तम नस्ल की गाय से एक साल में ही 4-5 भ्रूण तैयार किये जा रहे हैं। इससे गुणवत्तापूर्ण अधिक दूध देने वाली देशी गायों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और अनुपयोगी गायों की कोख का भी सदुपयोग हो रहा है। मप्र के पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का यह प्रयास पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रहा है।

प्रत्येक ग्राम में आवासीय आबादी आरक्षित, घर बनाने ऋण भी देगी सरकार

अब पंचायत में ग्रामीणों को मिलेंगे भूखंड

वंदना बृजेश परमार, उज्जैन।

राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 60 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया जाएगा। भूखंड पर मकान बनाने के लिए सरकार ऋण भी दिलवाएगी। भू-अभिलेख विभाग की अधीक्षक प्रीति चौहान ने बताया ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक राजस्व ग्राम में ग्रामीणों के लिए आवासीय प्रयोजन के लिए आबादी आरक्षित की गई है। कालांतर में जनसंख्या बढ़ने पर यह भूमि कम पड़ने लगी है। इसलिए गांवों में उपलब्ध दखलरहित भूमि को चिन्हित कर पात्र परिवारों को 60 वर्ग मीटर के भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत भूखड के लिए कमजोर वर्ग के परिवार पात्र होंगे। एक परिवार में पति-पत्नि तथा पुत्र व पुत्री को पात्र माना गया है। आवेदक को भू-खंड प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव व

पटवारी को आनलाइन एसएएआरए एप पर आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद तहसीलदार द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर पात्र व अपात्र आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा। नियम व शर्तों के आधार पर प्राप्त आवेदकों को ही भूखंड प्रदान किए जाएंगे।

इन्हें नहीं होगी पात्रता

- जिन परिवारों के पास रहने के लिए स्वतंत्र रूप से मकान है।
- आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है।
- आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है।
- आवेदक परिवार को काई सदस्य शासकीय सेवा में है।
- जिस गांव में आवासीय भूखंड चाहता है,उस गांव में आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूचि में दर्ज नहीं है।

डोर टू डोर कचरा प्रबंधन के लिए 10 ग्रामों को ई-रिक्शा की सुविधा

भोपाल के गांवों में अब ई रिक्शा से उठेगा कचरा

संवाददाता, भोपाल। गांवों में डोर टू डोर कचरा प्रबंधन के लिए 10 ग्रामों को ई-रिक्शा की सुविधा प्रदाय की गई है। ग्रामों से निकलने वाले कचरे के बेहतर निपटान एवं प्रबंधन के लिए विकासखंड फंदा की 10 ग्राम पंचायतों तूमड़ा, सूखीसेवनिया, बालमपुर, खजूरी सड़क, कान्हासैया, कालापानी, मेंडोरी, आदमपुर छावनी एवं मुंगालिया छाप के लिए ई-रिक्शा प्रदाय किया गया है, जिससे सफाईकर्मी डोर टू डोर कचरा संग्रहित करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत हाल ही में ग्राम पंचायत, खजूरी सड़क में विधायक हुजूर रामेश्वर शर्मा के मुख्य आतिथ्य में ग्राम पंचायत, खजूरी सड़क, फंदाकलां एवं मुंगालिया छाप में सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं सेग्रेगेशन शेड निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत, मुंगालिया छाप, तूमड़ा एवं मेंडोरी में सेग्रेगेशन शेड निर्माण का भी लोकार्पण किया गया।

स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम 10 दिसंबर तक आना संभावित है। हमारा लक्ष्य है कि भोपाल जिला ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल रहे। पंचायत भवन को मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
विकास मिश्रा, सीईओ, जिपं, भोपाल

कृषकों ने सौंपा ज्ञापन, खरीद न होने पर अफसरों को दिया आंदोलन का अल्टीमेटम

बाजरा खरीद नहीं होने से परेशान किसान

अवधेश डंडोतिया, मुरैना।

समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद के लिए प्रशासन ने जिलेभर में खरीद केंद्र तो बना दिए, लेकिन इसके बाद इन खरीद केंद्रों से किसानों के बाजरा की खरीद नहीं की जा रही है। परेशान किसान अपनी उपज लेकर खरीद केंद्र तक पहुंचते हैं, किंतु एफएक्यू के हिसाब से उपज न बताकर इसे फेल कर दिया जाता है। आलम यह है कि यहां अभी तक रत्तीभर भी बाजरा की खरीद नहीं की गई है। जिस पर अब किसान आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने नायब तहसीलदार नरेश शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए तीन दिन में खरीद करने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके बाद एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी।

उल्लेखनीय है कि जिलेभर में प्रशासन ने बाजरा की खरीद के लिए 80 केंद्र बनाए हैं। समर्थन मूल्य पर 20 नवंबर से खरीद भी शुरू कर दी गई, लेकिन यह खरीद महज नाम के लिए शुरू हुई। यहां किसानों से बाजरा की उपज को खरीदा नहीं जा रहा है। इसकी वजह है कि प्रशासन ने जो एफएक्यू के तहत सैंपल भेजा है। वह इतना स्टैंडर्ड का है कि उसके मुकाबले स्थानीय किसानों की उपज नहीं है। ऐसे में सोसायटी पर

पहुंचने वाले लगभग हर किसान के बाजरे को फेल बताकर वापस किया जा रहा है। किसान इस संबंध में पूर्व में इकट्ठा होकर आवेदन दे चुके। जिसके बाद भी खरीद शुरू नहीं हो सकी तो भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह तोमर के नेतृत्व में सभी किसान इकट्ठा होकर तहसील कार्यालय पहुंच गए। जहां नायब तहसीलदार नरेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर तीन दिन में बाजरा की खरीद शुरू नहीं की जाती है तो सभी किसान एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगें और सड़कों पर उतरकर चक्काजाम किया जाएगा।

महज चार हजार टन खरीद

यहां 20 नवंबर से बाजरा की खरीद चालू की गई। यह खरीद नाममात्र के लिए ही की गई है। स्थिति यह है कि जहां डेढ़ लाख टन से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 13 दिन में महज चार हजार टन ही बाजरा की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा सकी है। जिसमें ज्यादातर खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू तक नहीं हो पा रही है। वजह सिर्फ एक ही है, कि यहां बाजरा एफएक्यू मानक के अनुरूप नहीं है। जिस पर सोसायटी संचालक किसानों के बाजरा को फेल कर वापस कर रहे हैं।

बारिश ने बिगाड़ी रंगत

यहां किसानों के बाजरा की गुणवत्ता में कमी आने की एक बड़ी वजह है कि बाजरा कटने के बीच ही तेज बारिश हो गई। किसानों का बाजरा खेतों में रखा हुआ ही भीग गया। जिलेभर में यह हालात बने। जिसकी वजह से ज्यादातर किसानों के बाजरा उपज का रंग सांवला हो गया। यह बात प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता है। लेकिन इसके बावजूद इस स्तर का यहां खरीद केंद्रों पर सैंपल भेजा गया है कि किसानों की उपज उसके बराबर नहीं हो रही। जिसकी वजह से खरीद केंद्र इसे फेल कर रहे हैं।

-कृषि आयुक्त, एसीएस और मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक पहुंचे गांव

रायसेन का बासमती चावल जा रहा अमेरिका और यूरोप

संवाददाता, रायसेन।

कृषि उपज मंडी रागिति बरेली की अनुज्ञप्तिधारी फर्म दावत फूडस लिमिटेड द्वारा ग्राग बाड़ी जिला रायसेन में गत दिवस वार्षिक कार्यकम उमंग-2021 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मप्र के कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह, कृषि एवं सहकारिता के अपर मुख्य सचिव अजीत कसरी, मप्र कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक विकास नरवाल, रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे, दावत फूड्स लिमिटेड के सीएमडी विजय अरोरा और कृषि विभाग के अधिकारी नागरिक व भारी संख्या में किसान मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान एसीएस ने परिचर्चा के

माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रायसेन जिले में उत्पादित बासमती धान से बने चावल का अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में निर्यात हो रहा है। इसलिए एक जिला एक फसल योजना के अंतर्गत रायसेन जिले के लिए बासमती धान फसल का चयन किया गया है। इस फसल के उत्पादन के लिए खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग व बोवनी से लेकर विक्रय तक की सभी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिससे किसानों द्वारा कम लागत में अधिक से अधिक बासमती धान का उत्पादन कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। परिचर्चा में एसीएस ने किसानों से व्यक्तिगत परिसंवाद करते हुए किसानों के सभी सवालों वा आशंकाओं का समाधान किया। जिससे किसान खुश हो गए। मंडी बोर्ड भोपाल के उपस्थित अधिकारियों द्वारा भी किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा/समस्या नहीं हो इस संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उन्नत कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त होने से उपस्थित किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

-कुलपति बोले-स्वास्थ्य व स्वच्छता के कार्यों को प्रदान की जाएगी गति

-ग्रामोदय व डीआरआई के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन

गोद लिए गांव होंगे स्वस्थ्य-स्वच्छ-साक्षर

संवाददाता, चित्रकूट।

वर्षों पूर्व भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के साथ 110 किमी की पदयात्रा में मोहकमगढ़ आना हुआ था। अब प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल की प्रेरणा और उनकी सकारात्मक सोच के कारण ग्रामोदय विवि-डीआरआई व सद्गरू के साथ मिलकर प्रथम चरण में स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्य प्रारंभ करने जा रहा है। यह बात महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि के कुलपति प्रो. भरत मिश्रा ने मोहकमगढ़ गांव में आयोजित चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन दीनदयाल शोध संस्थान, आरोग्यधाम प्रकल्प एवं ग्रामोदय विवि के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। कुलपति ने कहा कि नानाजी की परिकल्पना थी कि ग्रामों का उत्थान हो, इसके लिए नाना जी ने विश्व ग्रामे प्रतिष्ठिम के बोध वाक्य को आत्मसात कर ग्रामोदय विवि की स्थापना इस क्षेत्र में की थी। उन्होंने कहा कि मैं भी गांव से ही हूं इसलिए यहां की समस्याओं को समझता हूं। जीवन में स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी बाकी अन्य कार्य भी सुगमता से होंगे। मोहकमगढ़ के ग्राम विकास के लिए ग्रामोदय विवि, दीनदयाल शोध संस्थान एवं सदुरु सेवा संस्थान ने साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है।

राज्यपाल ने किया था मार्गदर्शन- स्वास्थ्य, स्वच्छता और साक्षरता के माध्यम से गांव के विकास को गति प्रदान करने की दिशा में प्रभावी कार्य करते हुए हर क्षेत्र में मोकमगढ़ को खुशहाल बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को राज्यपाल मोहकमगढ़ आए थे और यहां की परिस्थितियों और चुनौतियों से अवगत होने के बाद मुझे मोहकमगढ़ गांव के लिए विकास कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दिए थे।

बच्चों को पढ़ाने का आह्वान

कुलपति प्रो.भरत मिश्रा ने गांव में अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा देने के लिए अभिभावकों आह्वान करते हुए कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए गांव स्तर पर, सुरेंद्र पाल ग्रामोदय एवं उच्च शिक्षा के लिए ग्रामोदय विवि है। जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। यहां के ग्रामवासियों को समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, यह प्रयास भी होगा, ग्रामोदय विवि नानाजी की संकल्पना के अनुरूप हो।

गांव शिक्षा में पिछड़ा

दीनदयाल शोध संस्थान आरोग्यधाम की डॉ. भारती श्रीवास्तव ने कहा कि यह गांव शिक्षा एवं स्वास्थ्य में पिछड़ा है। नानाजी का कार्य चित्रकूट क्षेत्र की 50 किमी परिधि में दीनदयाल शोध संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा , रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आदि क्षेत्र में कार्य करता है। आज यहां आयोजित स्वास्थ्य शिविर का एकमात्र लक्ष्य है कि स्थानीय स्तर पर जिन स्वास्थ्य समस्याओं का निदान हो सकता है उनका किया जा रहा है। अन्यथा आरोग्यधाम निदान सदन में रेफर कर निदान किया जाएगा।

यह रहे मौजूद

कुलपति प्रो. भरत मिश्रा ने सबसे पहले भारत माता, नानाजी देशमुख एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। संचालन दूरवर्ती शिक्षा केंद्र के निदेशक डॉ. वीरेंद्र व्यास ने किया। प्रबंधन विभाग के डॉ. देवेंद्र पांडेय, आयुर्वेद प्रभारी डॉ. राकेश श्रीवास्तव, प्राध्यापक डॉ. उमेश शुक्ला, डेंटल चिकित्सक डॉ. रेवती, वंदना, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. राजीव शुक्ल, विनोद गुप्ता, अनिल श्रीवास्तव, श्रीकांत, शारदा प्रसाद, कामता गौतम, गणेश गौतम आदि ने स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से सामान्य चिकित्सा एवं डेंटल चिकित्सा सेवाएं दी।

मशरूम की खेती से महिलाओं को बनाया जाएगा स्वाबलंबी

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं मैं पोषण सुधार एवं आजीविका का साधन बना कर आथिज़्क रूप से मजबूत बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी खेती से महिला सशक्तिकरण किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर रजनी नानोटकर मशरूम का उत्पादन करती है और कई महिलाओं का ग्रुप बनाकर मशरूम खेती की ओर कदम बढ़ावा भी दे रहीं है। डॉ बीएस किरार प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख ने बताया कि मशरूम खाने की सलाह कई डॉक्टर भी देते हैं, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले आवश्यक तत्व और विटामिन शरीर को दुरुस्त रखने में बेहद अहम भूमिका अदा करते हैं। मशरूम में 22-35 प्रतिशत उच्च कोटि की प्रोटीन होती है जो पाचन शक्ति को 60-70 प्रतिशत तक बढ़ा देता है। अमीनो अम्ल जैसे मेथिओनिन, ल्युसिन आइसो ल्युसिन, लाइसिन, थ्रिओनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, हिस्टिडिन और अर्जिनिन यह अमीनो अम्ल दूसरे अनाजों में कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। इसमें कलवासिन, म्युनाइड, लेटीनिन क्षारीय एवं अम्लीय प्रोटीन मानव शरीर में ट्यूमर बनने से रोकती है। इसमें 4-5 प्रतिशत पाए जाने वाले कार्बोहइड्रेट जिसमें मैनीटाल, हेमिसेलुलोज, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल एवं शर्करा के अवशोषण को कम करता है। 100 ग्राम मशरूम से 35 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सोडियम साल्ट, बसा और कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगियों के लिए हानिकारक पदार्थ कम होने से गुर्दा हृदय के रोगियों के लिए आदर्श आहार है। शर्करा की मात्रा 0.5 प्रतिशत होने से मधुमेह रोगियों के लिए उचित आदर्श भोजन होता है। मनुष्य में होने वाले जीवाणु विरोधी क्षमता प्युरीन, पायरीमिडीन, म्युनान, टरपेनाइड जैसे तत्व जो मशरूम में पाए जाते हैं। मशरूम पेट की

-कृषि विज्ञान केंद्र ने किया बकरी कृमिनाशी अभियान आगाज

शिवपुरी में बकरी पालन की असीम संभावनाएं

खेमराज मौर्य, शिवपुरी।

जिले की सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिकोण से बकरी पालन की असीम संभावनाएं हैं। जिले में तीन लाख से अधिक बकरियों की संख्या है। जिनके पालन में बड़ी संख्या में किसान और भूमिहीन मजदूर लगे हुए हैं। बावजूद इसके बकरी पालकों में जागरूकता एवं जानकारी के अभाव के कारण बकरियों का स्वास्थय अच्छा नहीं है। इस कारण उनसे क्षमता के अनुरूप मांस एवं दुग्ध उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। जिले की बकरियां कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं। बकरी पालक अपनी बकरियों को अंत: परजीवियों (पेट के कीड़ों) की दवा तक नहीं पिलाते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उक्त जानकारी एक सर्व के से कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी

द्वारा प्राप्त की गई है। इस समस्या को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जिले में बकरियों को पेट के कीड़ों से बचाने के लिए केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह के नेतृत्व में कृमिनाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. सिंह ने बताया कि बकरी पालकों में जागरूकता पैदा करने के लिए करैरा ब्लॉक के मामोनीखुर्द गांव को बकरी गांव के रूप में गोद लेकर बकरी कृमिनाशी अभियान की शुरुआत की गई है। गांव में अब तक 400 से अधिक बकरियों को कृमिनाशक दवा घर-घर जाकर उनके शरीर भार के अनुसार पिलाई जा चुकी है जिसका सकारात्मक परिणाम बकरी पालकों के बीच देखने को मिल रहा है। सिंह ने बताया कि आगे भी पूरे वर्ष 3 से 4 माह के अंतराल पर कृमिनाशक दवा नि:शुल्क पिलाई जाती रहेगी। इसके साथ ही पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के तहत मामोनीखुद गांव की बकरी पालक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालक की जानकारी से भी अवगत कराया जाएगा। जिससे बकरी पालन गरीबों की आय का साधन बन सके। इसके साथ ही सतनवाड़ा के कांकर गांव में भी बकरी पालकों को कृमिनाशी अभियान के तहत दवा पिलाई गई है। आयोजित कार्यक्रम में केंद्र के प्रमुख डॉ. एसपी सिंह द्वारा बकरियों को दवा पिलाई गई। जिसमें केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. एएल बसेड़िया, डॉ. एनके कुशवाहा एवं वीपीएस कुशवाह द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

तेज हवा-आंधी आने पर भी नहीं झुकती, एक एकड़ में 40 किलों बीज से 20 क्विंटल उत्पादन

खरगोन को मिली गेहूं की दो नई किस्में

» सामान्य गेहूं का उत्पादन प्रति एकड़ 10 क्विंटल ही होता है

» 120 दिन में पकेगी 40 से 48 क्विंटल हेक्टेयर तक उपज

संजय शर्मा, खरगोन।

खरगोन जिले में इस वर्ष कृषि विभाग को गेहूं की दो नई किस्म प्राप्त हुई। जिले को पहली बार मिली गेहूं की किस्म कम पानी में बेहतर उत्पादन वाली है। कृषि विभाग द्वारा फिलहाल अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त दोनों किस्में जिले के लिए बेहतर साबित होगी। फिलहाल अनुसंधान केंद्र से प्राप्त हुआ बीज जिले की बीज उत्पादन समितियों को ही दिया गया है। कृषि विभाग के उपसंचालक एमएल चौहान ने बताया कि जिले में गेहूं की जेडब्ल्यू (एमपी) 3288 और राज-4238 किस्म पहली बार लगाई है। दोनों किस्म जिले में सीड्स प्रोग्राम के तहत बीज समितियों को वितरित की गई है। उन्होंने बताया कि गेहूं का जेडब्ल्यू 3288 बीज करीब 30 क्विंटल और राज-4238 किस्म करीब 40 क्विंटल प्राप्त हुआ है। फिलहाल यह बीज किसानों को वितरित नहीं किया गया है। बीज समितियों द्वारा इसका उत्पादन कर जांच के बाद किसानों को आगामी वर्ष में दिया जाएगा।

2013 में तैयार किया बीज

कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि दोनों किस्म जिले के वातावरण को देखते हुए अनुकूल है। गेहूं की जेडब्ल्यू 3288 किस्म 110 दिन में तैयार हो जाती है। जिससे लगभग 55 से 65 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त हो सकती है। यह किस्म कम पानी और तेज हवा-आंधी आने पर भी नहीं झुकती है। इसके दाने बड़े होते हैं। दाने छिंटकते नहीं है। गेहूं की यह किस्म गेरूआ रोग के प्रतिरोधी है। इसी प्रकार पहली बार जिले में गेहूं की नई किस्म राज-4238 की भी बोवनी की गई है। यह राजस्थान की किस्म है और 2013 में यह बीज तैयार किया गया है।

120 दिन फसल पककर तैयार

अभी यह किस्म पूरे देश में कृषि कॉलेजों एवं अनुसंधान केंद्रों में ही उपलब्ध है। उपसंचालक ने बताया कि अन्य वेरायटी की तुलना में इसका उत्पादन अधिक होता है। यह एक एकड़ में 40 किलों बीज के हिसाब से 20 क्विंटल उत्पादन होगा। सामान्य गेहूं का उत्पादन प्रति एकड़ 10 क्विंटल ही हो पाता है। रेतीली भूमि में भी अच्छा उत्पादन दे सकता है। यह किस्म 115 से 120 दिन में पक कर 40 से 48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे सकती है।

कम बारिश से बढ़ा चने का रकबा

खरगोन में इस वर्ष कम बारिश होने से गेहूं के रकबे में कमी आई है। वहीं चने के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष जिले में कृषि विभाग द्वारा गेहूं की बोवनी के लिए 2 लाख 20 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है। जबकि गत वर्ष 2 लाख 45 हजार 976 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई थी। इस प्रकार चने की बोवनी का लक्ष्य 1 लाख 20 हजार हेक्टेयर तय किया गया है। जबकि गत वर्ष 95 हजार 594 हेक्टेयर में चने की बोवनी की गई। इस वर्ष जिले में 1 लाख 50 हजार हेक्टेयर से क्षेत्र में चने की बोवनी होगी। वहीं गेहूं की बोवनी 2 लाख हेक्टेयर से कम क्षेत्र में होने की संभावना है।

खरगोन में 29 बीज समितियां

जिले में 29 बीज उत्पादन समितियां है। जिले को प्राप्त हुई गेहूं की दोनों किस्म के बीच संबंधित समितियों को निर्धारित मात्रा में बीज उत्पादन के लिए दिए है। समितियों द्वारा बीज उत्पादन करने के बाद किसानों को बीज दिया जाएगा। आगामी वर्ष से किसानों को निर्धारित मात्रा में बीज देकर बीज उत्पादन को बढ़ाया जाएगा।

इंदौर में ऊर्जा का भंडार बना कचराघर

कचरे को बना दिया कमाई का आधार

सीएनजी से सिटी बसों को चलाएंगे

इंदौर। स्वच्छता के नवाचार अब मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम के संस्कारों में ढलते जा रहे हैं। देश में पहली बार संयंत्र लगाकर बड़े स्तर पर यहां गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का काम शुरू हुआ है। परिणाम स्वरूप, यहां ट्रेंचिंग ग्राउंड में पसरा कचरा ऊर्जा भंडार बन चुका है। योजना प्रतिदिन 500 टन गीले कचरे से 18 हजार किलो गैस बनाने की है। फिलहाल, ट्रेंचिंग ग्राउंड में गैस तैयार करने का प्रथम चरण शुरू है। बायो सीएनजी संयंत्र के डाइजेस्टर में गोबर व गीला कचरा डालकर कल्चर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। दिसंबर के अंत तक कल्चर तैयार होगा। वर्तमान में शहर में कबीटखेड़ी और चोइथराम मंडी में संचालित संयंत्रों से भी कल्चर लाकर यहां मिलाया गया है। इसके बाद इसमें प्रतिदिन 10 से 15 टन गीला कचरा मिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जनवरी के अंत तक शुद्ध बायो सीएनजी तैयार होने लगेगी, जो वाहनों के काम आएगी। संयंत्र में तैयार गैसों से शहर में 400 सीएनजी बसों के संचालन की तैयारी है, जो अगले दो महीने में यहां आएंगी। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रतिदिन चोइथराम मंडी के संयंत्र में 20 टन व कबीटखेड़ी में 15 टन गीले कचरे से क्रमश: 600 व 350 किलो गैस तैयार हो रही है। 80 फीसद गैस से प्रतिदिन करीब आठ सिटी बसों का संचालन हो रहा है। शेष गैस आटो रिक्शा व अन्य वाहन को दी जाती है।

बसों के आने के पहले संयंत्र में गैस तैयार होने लगेगी। संयंत्र में तैयार होने वाली 50 प्रतिशत गैस का उपयोग सिटी बसों को चलाने में होगा। शेष गैस अवंतिका गैस एजेंसी को दी जाएगी, जो अन्य वाहनों को इसे उपलब्ध कराएगी। बचे अपशिष्ट से खाद बनाई जाएगी।

अनूप गोयल, कार्यपालन यंत्री, नगर निगम, इंदौर

मौसम परिवर्तन से उत्पादन में कमी, गुणवत्ता प्रभावित होने से नहीं मिलेगा भाव

बारिश में भीगी लाल मिर्च, किसान परेशान

मदन काबरा, कुक्षी।

क्षेत्र में रिमझिम बारिश ने खलिहानों में सूख रही सैकड़ों क्विंटल लाल मिर्च फसल को भिगो दिया है। इससे मिर्च की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ भाव में कमी आने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे भी इस साल हर माह मौसम में बदलाव के चलते लाल मिर्च का उत्पादन क्षेत्र में 50 फीसद भी नहीं हुआ है। ऐसे में बिन मौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। कुक्षी तहसील की दूसरी मुख्य फसल है मिर्च, लेकिन इस साल जुलाई से ही लगातार मौसम के उतार-चढ़ाव के चलते फसल का उत्पादन लगातार प्रभावित होता रहा है। गत साल के मुकाबले इस साल महज 50 फीसद ही फसल का उत्पादन हुआ है। इसके चलते किसानों को आर्थिक नुकसान का पहले से ही सामना करना पड़ रहा है।

खेतों से लाल गीली मिर्च को मंडी में बेचने के पहले खुले में सुखाना होता है। मिर्च की यह फसल सूख जाने के बाद ही मंडी में बिकती है।

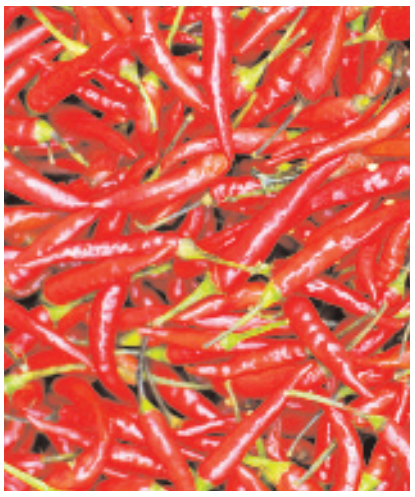

इसके खरीदार मिलते हैं। लाल मिर्च की फसल को आप किसी बंद कमरे या गोदाम में नहीं रख सकते हैं या सुखा सकते हैं, क्योंकि यह सड़ने लग जाती है। ऐसे में किसानों ने खलिहान में खुले में सूखने के लिए यह फसल रखी थी। अब भीग जाने से मिर्च गुणवत्ता खो देगी।

अब तक नहीं बना कोल्ड स्टोरेज

एक दशक पहले कुक्षी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान सीएम शिवराजसिंह ने कृषि उपज मंडी के प्रांगण में मिर्च व केले की फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने की घोषणा की थी, जिसे अब तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। अब तो कुक्षी के समीप ग्राम चोरबावड़ी में एक बडे प्रांगण में मिर्च की नवीन मंडी भी बन गई है। जहां कोल्ड स्टोरेज के लिए काफी जमीन उपलब्ध है। उसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर एक कोल्ड स्टोरेज बन जाए, तो किसान अपनी कच्ची फसल को वहां रखकर इस तरह के मौसम परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए!

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)